P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-8* ISSUE-7* March- 2021
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

भारतीय वाणिज्यिक बैंकिंग में गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियों की प्रवृत्ति तथा इनके निर्धारक तत्वों का विश्लेषण

Analysis of The Trend of Non-Performing Assets and Their Determinants In Indian Commercial Banking

Paper Submission: 04/03/2021, Date of Acceptance: 24/03/2021, Date of Publication: 25/03/2021

रामेश्वरी मीना
सहायक आचार्य,
अर्थशास्त्र विभाग,
बाबा नारायणदास राजकीय कला महाविद्यालय,
चिमनपुरा, शाहपुरा,
जयपुर, राजस्थान, भारत
एवं
शोधार्थी,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर, राजस्थान, भारत

सारांश

बैंकिंग क्षेत्र किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की मुख्य धुरी है। वर्तमान परिदृश्य में गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियाँ (NPAs) भारत तथा सम्पूर्ण विश्व में बैंको के सामने मुख्य चुनौती है। NPAs बैंकिंग उद्योग पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डालते है। इस पेपर में अनुसूचित व्यापारिक बैंको में वर्ष 2010–18 की अवधि के लिए गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियों की प्रवृत्ति का विश्लेषण किया गया हे। इसके अलावा NPAs के निर्धारक तत्वों का भी परीक्षण किया गया है। इस अध्ययन के पश्चात् यह पाया गया है कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में NPAs की मात्रा में निरन्तर वृद्धि हो रही है। यह भी निष्कर्षित किया गया है कि NPAs की वृद्धि हेतु अनेक कारक उत्तरदायी है तथा ये बैंक–विशिष्ट और अर्थव्यवस्था विशिष्ट होते है।

The banking sector is the main axis of the economy of any country. In the current scenario, the non-performing assets (Chhattisgarh) is the main challenge before banks in India and all over the world. The six have a significant impact on the banking industry. This paper analyzes the trend of non-performing assets in scheduled commercial banks for the period 2010–18. Apart from this, deterministic elements of the school have also been tested. After this study, it has been found that there is a continuous increase in the amount of Chhattisgarh in the Indian banking sector. It has also been concluded that many factors are responsible for the growth of the school and are bank-specific and economy-specific.

मुख्य शब्द : वृहद्–आर्थिक कारक, GDP बेरोगजारी दर, गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियाँ, ब्याज दर।
Macroeconomic Factors, Real Unemployment Rate, Non-Performing Assets, Interest Rate.

प्रस्तावना

वर्ष 1991 में आर्थिक उदारीकरण के प्रथम चरण के पश्चात् बैंकिंग उद्योग में आमूलचूल परिवर्तन हुए। बैंकिंग उद्योग किसी भी अर्थव्यवस्था हेतु रीढ़ की हड्डी का काम करता है। बैंकिंग क्षेत्र की विफलता का अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। बैंकिंग क्षेत्र द्वारा जनता की बचतों को जमाओं के रूप में संग्रहित किया जाता है तथा इनको ऋणों व अग्रिमों के रूप में विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों जैसे– कृषि, उद्योग आदि को प्रदान किया जाता है। इस प्रकार बैंको द्वारा दिए गए ऋण व अग्रिमों द्वारा व्यावसायिक उद्यमों की अल्पकालीन व दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सहायता मिलती है। बैंकिंग व्यवसाय द्वारा अनेक जोखिमों का सामना किया जाता है जैसे– साख जोखिम, तरलता जोखिम, ब्याज जोखिम, बाजार जोखिम परिचालन जोखिम तथा प्रबंधन जोखिम आदि। इन सभी जोखिमों में सबसे महत्वपूर्ण जोखिम ऋणों की रिकवरी है। उधार प्रक्रिया साख जोखिम सृजित करती है, जो उधारकों की विफलता से उत्पन्न होती है। उधारकों द्वारा जब किसी ऋण पर ब्याज व किश्त का भुगतान 90 दिनों की अवधि से अधिक समय तक नहीं किया जाता है, तो इस ऋण या परिसम्पत्ति को गैर–निष्पादित परिसम्पत्ति के रूप में माना जाता है। गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियाँ (NPAs) बैंको के प्रदर्शन को दर्शाती है। NPAs का उच्च स्तर साख डिफॉल्ट की अधिकतम संभावना को प्रकट करता है। जिससे बैंकों की लाभदायकता तथा नेटवर्थ प्रभावित होता है तथा परिसम्पत्तियों के मूल्य भी कम होते है।

वर्तमान परिदृश्य में NPAs बैंको की आधारभूत वित्तीय समस्या है। वसूली निष्पादन को सुधारने के लिए ठोस उपाय होने चाहिए। बढ़ते NPAs के पीछे मुख्य कारण लक्ष्य केन्द्रित दृष्टिकोण, विलफुल डिफॉल्टर तथा ऋण खातों का अप्रभावी निरीक्षण है।

साहित्यावलोकन

NPA एक ज्वलंत विषय है तथा अनेक लेखकों द्वारा NPA के कारणों इसके द्वारा उत्पन्न समस्या, समाधान हेतु उपायों तथा इसका बैंकिंग क्षेत्र पर प्रभावों का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। पेपर के इस भाग में इससे सम्बंधित विभिन्न उपलब्ध साहित्यों की समीक्षा की जायेगी।

सैकत घोष रॉय (2014) ने इस पेपर में भारतीय बैंको में NPAs की प्रवृत्तियों तथा इसके निर्धारकों का विश्लेषण किया था। पैनल प्रतीपगमन द्वारा NPA पर चयनित मैक्रोइकॉनॉमिक चरों के प्रभाव का मूल्यांकन किया गया। पैनल प्रतिगमन परिणाम स्पष्ट करता है कि GDP विकास, विनिमय दर में बदलाव और वैश्विक अस्थिरता का भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के NPA स्तर पर अत्यधिक प्रभाव है।

सबत कुमार दिगल तथा एलिना कानूनगों (2015) का यह पेपर बैंकिंग क्षेत्र के प्रणालीगत महत्व को देखते हुए सामान्य रूप से भारतीय बैंकों के NPA और तनावग्रस्त परिसम्पत्तियों के स्तर और विशेष रूप से भारतीय स्टेट बैंक के अध्ययन का प्रयास करता है। उन्होंने इस अध्ययन के पश्चात् सुझाव दिया कि NPA के खतरे से अलगाव में नहीं लड़ा जा सकता है तथा माँग व आपूर्ति दोनों पक्षों को सम्बोधित किया जाना चाहिए, जिसमें अल्पकालिक उपलब्धियों और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केन्द्रित किया जाए।

चेतन दुधे (2017) ने इस पेपर में चयनित बैंको जैसे–स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (SBI), बैंक ऑफ इण्डिया, युनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया में NPAs की प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया था। यह NPA से निपटने के लिए बैंको द्वारा पालन की जाने वाली नीतियों पर भी प्रकाश डालता है और बैंकिंग क्षेत्र में NPA की त्वरित वसूली के लिए बहु–आयामी रणनीति का सुझाव भी देता है। उन्होंने इस अध्ययन के पश्चात् पाया कि SBI और PNB को छोड़कर अन्य सभी बैंक अपने सकल गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियों और शुद्ध लाभ के बीच एक नकारात्मक संबंध प्रदर्शित करते है।

पीटर स्टीफन किंगू तथा अन्य (2018) के इस अध्ययन ने सूचना विषमता सिद्धान्त और बुरे प्रबंधन परिकल्पना का उपयोग करके बैंक के लाभ पर गैर–निष्पादित ऋण के प्रभाव की जांच का प्रयास किया था। इस अध्ययन में तजांनिया के 16 वाणिज्यिक बैंको के पैनल डेटा (2007 से 2015) का उपयोग करके कार्य कारण अनुसंधान डिजाइन को अपनाया गया। इसके अलावा वर्णनात्मक सांख्यिकी और अनेक प्रतीपगमन विश्लेषण आकलन विधियों को भी प्रयोग किया गया। अध्ययन में पाया गया कि गैर–निष्पादित ऋण की घटना नकारात्मक रूप से तंजानिया और वाणिज्यिक बैंको की लाभप्रदता के स्तर से जुड़ी हुई है।

शोध प्रविधि एवं उद्देश्य

अध्ययन के लिए अनुसूचित व्यापारिक बैंकों का चयन किया गया है तथा अध्ययन हेतु द्वितीयक श्रेणी के आंकड़ों का संग्रहण वर्ष 2010 से 2018 तक की अवधि के लिए किया गया है। विभिन्न प्रकार के शोध पत्रों तथा आलेखों को अध्ययन के दौरान संदर्भित किया गया है। आंकड़ों का संग्रहण मुख्य रूप से विभिन्न वर्षों की RBI रिर्पोटों से किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य

वाणिज्यिक बैंकों में NPAs की प्रवृत्ति का विश्लेषण करना। NPAs के निर्धारक तत्वों का विश्लेषण करना।

विश्लेषण

गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियों की प्रवृत्तियाँ

सभी लोन परिसम्पत्तियों का योग, जिनको RBI के निर्देशों के अनुसार NPAs के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, उन्हें सकल NPA कहते है। सकल NPAs हेतु अनेक प्रावधान करने पड़ते है, यदि इन प्रावधानों को सकल NPAs में से घटा दिया जाये, तो शुद्ध NPAs प्राप्त होता है। निम्न तालिका में अनुसूचित व्यापारिक बैंको (SCBs) में (NPAs) की प्रवृत्तियों को दर्शाया गया है।

तालिका–1

ScBs में NPAs की प्रवृत्तियाँ (रू. करोड़ में)

वर्ष	सकल NPAs	शुद्ध NPAs	सकूल NPAs का कुल परिसम्पत्तियों प्रतिशत	शुद्ध NPAs का कुल परिसम्पत्तियों से प्रतिशत
2010	84700	38700	1.4	0.7
2011	97900	41800	1.3	0.2
2012	142900	65200	1.6	0.2
2013	194000	98600	2.0	0.4
2014	263000	142600	2.4	0.4
2015	322900	175800	2.7	0.2
2016	611600	349800	4.7	0.3
2017	790200	433000	5.6	0.3
2018	1039700	520700	6.8	0.2

Sources : RBI's report on trends and progress of Banking in India.

उपर्युक्त तालिका से समग्र अध्ययन एवं विश्लेषण से स्पष्ट है कि अनुसूचित व्यापारिक बैंको (SeBs) में सकल NPAs तथा शुद्ध NPAs दोनों की निरपेक्ष मात्रा में सतत् रूप से वृद्धि की प्रवृत्ति पायी जाती है। वर्ष 2010 में इन बैंको में सकल तथा शुद्ध NPAs की मात्रा क्रमशः 84700 करोड़ रू., 38700 करोड़ रू. थे, जो वर्ष 2018 में बढ़कर क्रमशः 1039700 करोड़ रू., 520700 करोड़ रू. हो गयी है। सकल तथा शुद्ध NPAs का कुल परिसम्पत्तियों से प्रतिशत अनुपात का परीक्षण करने से स्पष्ट है कि इनमें मिश्रित उच्चावच की प्रवृत्ति पायी जाती है। सकल NPAs का कुल परिसम्पत्तियों से प्रतिशत अनुपात वर्ष 2010 में 1.4 प्रतिशत था, जो वर्ष 2018 में बढ़कर 6.8 प्रतिशत हो गया है। यह भी स्पष्ट है कि शुद्ध NPAs का कुल परिसम्पत्तियों से प्रतिशत अनुपात, सकल NPAs का कुल परिसम्पत्तियों से प्रतिशत अनुपात की तुलना में कम है, इससे परिलक्षित होता है कि सकल NPAs हेतु बैंको द्वारा अनेक प्रावधान (Provision) किये जाते है। परन्तु बैंकों द्वारा अधिक प्रावधान करने के कारण इनके पास निधियों की कमी होती है, जिसके कारण बैंकों द्वारा साख–सृजन कम होने की वजह से इनकी लाभदायकता प्रभावित होती है।

SCBs में सकल तथा शुद्ध NPAs दोनों के उच्च स्तर तथा इनकी बढ़ती हुई प्रवृत्ति से स्पष्ट है कि सरकार तथा RBI द्वारा इनको प्रबन्धित तथा नियंत्रित करने हेतु और अधिक उपायों को अपनानें की आवश्यकता है।

गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियों के निर्धारक तत्त्व

गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियों के निर्धारक तत्वों को विभिन्न साहित्यों के अध्ययन के आधार पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है– वृहद् आर्थिक कारक तथा बैंक विशिष्ट कारक। वृहद् आर्थिक कारकों में GDP, मुद्रास्फीति, ब्याज दर, व्यावसायिक चक्र आदि को शामिल किया जाता है। अनेक शोधकर्त्ताओं ने NPAs तथा वृहद आर्थिक कारकों के बीच सम्बंध का अध्ययन किया। यह स्वीकार किया जाता है कि अर्थव्यवस्था के विस्तारवादी चरण में NPAs तुलनात्मक रूप से निम्न होते है क्योंकि उपभोक्ताओं तथा फर्मों की आय में वृद्धि होती है। इसलिए उनके द्वारा निश्चित समयावधि में भुगतान कर दिया जाता है। किन्तु रिसेशन अवधि के दौरान बैंक खराब छवि वाले उधारकों को भी ऋणों का आवंटन करते है, इसके फलस्वरूप खराब ऋणों में कई गुना वृद्धि होती है।

लिस तथा अन्य (2000) ने पाया कि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि NPAs पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, क्योंकि बढ़ते आय स्तर के कारण व्यावसायिकों द्वारा उनके ऋणों का भुगतान किया जाता है तथा NPAs घटता है। सब– सहारण देशों में स्फीतिकारी दबाव खराब ऋणों (bad loans) में वृद्धि करता है। बेरोजगारी की दर एक अन्य वृहद् आर्थिक कारक है, जो NPAs को प्रभावित करता है। इसका भी वही सम्बंध है, जैसा कि मुद्रास्फीति दर का है। कस्तुरीरंगन ने एक अध्ययन में यह जानने का प्रयास किया कि बढ़ती ब्याज दरों तथा बढ़ते NPAs के बीच क्या सम्बंध है। उन्होंने पाया कि बढ़ती ब्याज दरों तथा NPAs के बीच कोई सम्बंध नहीं है।

निष्कर्ष

उपरोक्त विश्लेषण एवं परिणामों से स्पष्ट कि अनुसूचित व्यापारिक बैंकों में गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियों की मात्रा में निरन्तर वृद्धि हो रही है। NPAs के निर्धारक तत्वों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियों के अनेक निर्धारक है। सभी बैंकों के लिए निर्धारक चरों के किसी एक सेट को निर्धारित नहीं किया जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ब्याज दर अशोध्य ऋणों (NPLs) को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, तथा निजी क्षेत्र के बैंको में अन्य चर महत्त्वपूर्ण निर्धारक है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *सैंकत घोष रॉय (2014) ''डिटरमिनेन्टस् ऑफ नॉन–परफॉर्मिंग एसेट्स इन इण्डिया–पेनल रिग्रेशन'' यूरेशियन जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स एण्ड फाइनेन्स, पेज–69–78*
2. *सबत कुमार दिगल तथा एलिना कानूनगों (2015), ''नॉन–परफॉर्मिंग एसेट्स एण्ड बैंकिंग स्ट्रेस– सम इश्यूज'' ASBM जर्नल ऑफ मैनेजमेन्ट।*
3. *चेतन दुधे (2017), ''इम्पैक्ट ऑफ नॉन– परफॉर्मिंग एसेट्स ऑन द प्रॉफिटबिलिटी ऑफ बैंक्स्–ए सलेक्टिव स्टडी'', एन्नलस् ऑफ फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स, पेज 307–314*
4. *पीटर स्टीफन किंगू तथा अन्य (2018), ''इम्पैक्ट ऑफ नॉन–परफॉर्मिंग लोनस् ऑन बैंक प्रॉफिटबिलिटी–एम्पीरिककल एविडेन्स फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक्स् इन तंजानिया'', इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एण्ड मैनेजमेन्ट।*
5. *एम वल्लीमल तथा मणिवन्नन (2018), ''ए स्टडी ऑन नॉन–परफॉर्मिंग एसेट्स एण्ड इट्स इम्पैक्ट ऑन पब्लिक सेक्टर बैंक्स् इन इण्डिया'', इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इन साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी (IJSRST)*
6. *फॉफैक तथा हिम्पोलिट (2005), ''नॉन–परफार्मींग लोनस् इन सब–सहारण अफ्रीकाः कैजुअल एनालिसिस एण्ड मैक्रोइकॉनॉमिक इम्पलिकेशन्स'', वर्ल्ड बैंक पॉलिसी*
7. *रिसर्च वर्किंग पेपर*
8. *bankreport.rbi.org.in*